MESSAGES FROM LOK SABHA .... *(Contd.)*

The Right to Information Bill, 2005

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary General of Lok Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Right to Information Bill, 2005, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 11th May, 2005."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

HALF AN HOUR DISCUSSION

Points arising out of the Answer given in the Rajya Sabha on the 2nd May, 2005, to Starred Question No. 524 regarding 'Promotion of Urdu Language in Bihar'.

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश): डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज आपने हमें उर्दू पर बात कहने का मौका दिया, क्योंकि किसी हाऊस में ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि उर्दू पर बात हो। 55 सालों से उर्दू का जो दर्द है, मैं उसे यहां बयान नहीं करूंगा, उर्दू क साथ जो ज्यादतियां होती रही हैं, नाईसाफियां होती रही हैं, मैं वह बयान नहीं करूंगा, क्योंकि वह बहुत लम्बी दास्तान है, उसके लिए बहुत वक्त चाहिए। मैं आज जो बात करूंगा, उसमें बिहार में उर्दू की भी बात करूंगा, लेकिन बिहार में जो उर्दू है, वह आइसोलेशन में नहीं है। आप सिर्फ बिहार में उर्दू को जिन्दा नहीं रख सकते, अगर पूरे हिन्दुस्तान में उर्दू का कत्ल होगा। अगर बिहार में उर्दू को जिन्दा रखना है तो रोजगार से उसे जोड़ना होगा, पूरे हिन्दुस्तान में उर्दू को उसका हक देना होगा। महोदय, इसलिए मैं पूरे हिन्दुस्तान के मसले को सामने रखते हुए बिहार की बात करूंगा। जो पिछली बातें हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा मैं आज की बात करता हूं कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, उसमें वादा किया गया कि उर्दू को उसका हक दिया जाएगा, जहां पर 10 फीसदी से ज्यादा उर्दू के बोलने वाले हैं, वहां पर उसको दूसरी जुबान बनाया जाएगा, स्कूलों में उसके पढ़ने का इंतजाम किया जाएगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एक साल हो गया, आपने उर्दू के लिए, कॉमन

मिनिमम प्रोग्राम के इस बुनियादी मसले को लागू करने के लिए, क्या कदम उठाए? आपके मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं? उर्दू को इंसाफ दिलाने के लिए, दूसरी जुबां बनाने के लिए आपने क्या इनीसएटिव लिए हैं? राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में उर्दू को बढ़ावा देने की बात कही थी, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। बजट में उर्दू का नाम लिया गया, लेकिन कोई आवंटन उसके लिए नहीं किया गया, उसके लिए कोई रकम मुकर्रर नहीं की गई। कहा गया कि टीचर्स लगाए जाएंगे। मेरे अजीज, आप उर्दू की बात करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता।

सब मेरे चाहने वाले हैं, मगर कोई नहीं।

मैं खुद इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं।

महोदय, उर्दू के साथ जो ज्यादती होती रही है, उसमें कुछ लोग यह कहते हैं कि चूंकि यह अकलियतों की जुबां है, मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूं। उर्दू अकलियतों की जुबां नहीं है, लेकिन कुछ लोग उर्दू के साथ जुल्म करते हैं, यह समझ कर कि अकलियतों की जुबां है और इसलिए शायद उर्दू खत्म हो गई, तो अकलियत भी जो हैं, वे कमजोर हो जाएंगी।

जुल्म उर्दू पर भी होता है इस निस्बत से,

लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं।

महोदय, गलतफहमी जो है, वह दूर होनी चाहिए। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने जो यह एक बहुत बड़ा सर्वशिक्षा अभियान का प्रोग्राम बनाया है, उसमें उर्दू को आप कहां जगह दे रहे हैं? उर्दू को उसमें कितना हिस्सा मिलने वाला है? क्योंकि उर्दू से जुड़े हुए लोग, उर्दू के पढ़ने वाले लोग जो हैं, उन पर पिछले 55-56 साल में जुल्म हुआ है। इसलिए आज उनका सबसे ज्यादा हक बनता है, वे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। अगर आपको पूरे देश को शिक्षित करना है, तालीम-याफ्ता बनाना है, तो उनके लिए आपको उर्दू पर ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। जब तक आप इसके लिए रकम मुकर्रर नहीं करेंगे, तब तक जो राज्य की सरकारें हैं, वे उस पर अमल नहीं करेंगी।

महोदय, यह जरूरी है कि उर्दू को रोजगार से जोड़ा जाए। जब तक उर्दू को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। उर्दू को रोजगार से आप कैसे जोड़ेंगे? आप उर्दू का टी॰वी॰ चैनल शुरू कीजिए। सारी जुबानों के शुरू हो गए, उड़िया का हो गया, बंगला का हो गया, लेकिन उर्दू का चैनल शुरू करने में आपको क्या तकलीफ है? उर्दू की कमजोरी यह है कि उर्दू पूरे हिन्दुस्तान में बोली जाती है। यह हिन्दुस्तान की छठी सबसे बड़ी जुबान है। कश्मीर से तमिलनाडु तक उर्दू के स्कूल हैं, उर्दू के बोलने वाले हैं, उर्दू के चाहने वाले हैं, लेकिन अभी भी कश्मीर के अलावा कोई स्टेट इसमें आगे नहीं है। इसलिए उर्दू के लिए कोई मांग करने वाला नहीं है, उर्दू के लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। उर्दू का टी॰वी॰ चैनल आप शुरू करेंगे, तो उससे रोजगार मिलेगा, उर्दू का रेडियो

स्टेशन शुरू करेंगे, तो उससे भी रोजगार मिलेगा। इस सबसे बढ़कर मैं यह कहना चाहूंगा कि जब तक उर्दू के टीचर्स नहीं होंगे, जब तक उर्दू पढ़ाने का इंतजाम नहीं होगा, रोजगार मिलेगा और न उर्दू होगी।

बिहार में जब 1986 में कांग्रेस की सरकार थी, जगन्नाथ मिश्र जी ने, मैं उनको आज याद करता हूं और उनको बधाई देता हूं, कि उन्होंने इसे दूसरी जुबां का दर्जा दिया था और हमें अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नजर आई थी कि उर्दू को एक नई जिंदगी मिलने वाली है। जब 1986 में इसे दूसरी जुबां बनाया गया, तो हुआ क्या? कि बिहार में 1986 में जगन्नाथ मिश्र जी ने उर्दू को जब दूसरी जुबां बनाया, तो 600 ट्रांसलेटर्स लगाए गए, 300 ट्रांसलेटर्स और 300 असिस्टेंट ट्रांसलेटर्स, लेकिन आज वे ट्रांसलेटर्स उर्दू का काम नहीं कर रहे बल्कि फाइलिंग करने का काम करते हैं। उनसे उर्दू का काम नहीं लिया जाता और उसके बाद से तो बिहार में कोई उर्दू का ट्रांसलेटर अपोइंट ही नहीं किया गया जिसे आप कहते, बहाल नहीं किया गया। पिछले 30 साल के अंदर आपने उर्दू का कोई ट्रांसलेटर बहाल नहीं किया, उन 600 के बाद में और उनमें भी जो रिटायर हुए, वे जाते गए। ये ट्रांसलेटर्स बी॰ए॰ ग्रेजुएट थे, लेकिन ग्रेजुएट के साथ क्या ज्यादती की, कि उनको आपने जो तनख्वाह दी, जो ग्रेड दिया, वह इंटर वाले को दिया जाता है दूसरा अगर कोई किसी पोस्ट पर ग्रेजुएट आ रहा है तो उसको तनख्वाह दूसरी मिलेगी और उर्दू का जो ग्रेजुएट होगा उसको तनख्वाह दूसरी मिलेगी। आपने साफ कर दिया कि उर्दू को हम दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे की जुबां समझते हैं, उर्दू पढ़ाने वालों को हम दूसरे दर्जे का समझते हैं। उर्दू में इम्तिहान देने वाले और काम करने वाले को बराबर का हक देने को हम तैयार नहीं है। हम उसके लिए भी तैयार थे, लेकिन वह भी आपने नहीं किया। जगन्नाथ मिश्र जी ने ऐलान किया था तमाम थानों के लिए, चूंकि थानों का काम बिहार में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के अंदर नॉर्थ इंडिया में सारे थानों का काम, पुलिस स्टेशन का काम, कोर्ट का काम 1947 तक, बल्कि 1955-56 तक उर्दू में होते रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उर्दू के लोग लगाए नहीं गए, तो पुराने सारे जो रिकार्ड पड़े हुए हैं, उन रिकार्ड में कोई जा नहीं सकता, इसलिए मिश्र जी ने कहा था कि हर थाने में कम से कम एक मुंशी या एक आदमी उर्दू जानने वाला लगाया जाएगा मैं आपसे बड़े अफसोस के साथ यह कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर कहीं किसी थाने में उर्दू जानने वाले को एपायंट नहीं किया गया। जब मैं बिहार की बात कर रहा हूं, तो यह मानकर चलता हूं कि पूरे देश की बात कर रहा हूं, जहां जहां उर्दू है।

महोदय, इस वक्त चूंकि बिहार का सवाल है, इसलिए मैं बिहार पर ही जोर दूंगा। आप कुछ स्कूलों में जो टीचर्स लगाने वाले थे, वे उर्दू के टीचर्स आपने नहीं लगाए। आज भी हालत यह है कि 9000 जगह खाली हैं उर्दू के टीचर्स की, यानी 9000 लोगों को आप नौकरी दे सकते थे। उर्दू वाले उर्दू में बी॰ ए॰, एम॰ ए॰ करने के बाद भी भूखे मर रहे है। उन्हें अपना पेट काट कर उर्दू को जिन्दा रखना पड़ा रहा है, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी गई। बिहार के अन्दर 9000 टीचर्स की जगह खाली

है, वे टीचर्स नहीं लगाए गए। बिहार में 95 प्रतिशत जो गवर्नमेंट हाई स्कूल हैं, उनमें उर्दू टीचर नहीं हैं। उर्दू ज़बान के जो बच्चे हैं और जो उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उन्हें उर्दू पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। जो टीचर रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह दूसरे उर्दू के टीचर नहीं लगाए जा रहे हैं, तो सूरत-ए-हाल यह है।

मदरसों के लिए आपने कहा था कि कि 2900 मदरसे मंजूरशुदा हैं, लेकिन उन मदरसों के उस्ताद भी 15 वर्षों से सड़कों पर हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, पिछले दो वर्ष से उन्हें तरख्वाहें नहीं मिली। आपने बीस साल पहले बिहार में मज़हर-उल-हक़ अरबी-फारसी-उर्दू यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया था, वह आज तक किताबों में ही है। पिछले दिनों सुना कि किसी शर्फुद्दीन साहब को वाइस चान्सलर बना दिया गया, लेकिन अभी तक उनका कोई आफिस नहीं है, कोई कैम्पस नहीं है, यह सब आपने उर्दू के साथ किया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हम मदरसों की बात करते हैं, अगर सारे मदरसों को किसी उर्दू युनिवर्सिटी से एफिलिएट कर दिया जाए, तो उन मदरसों के बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलेंगे । वे जब उन मदरसों से पढ़ कर कॉलेज में आएंगे, तो ग्रेजुएशन कर सकेंगे, रोजगार ले सकेंगे और आगे जाकर यूज़फुल शहरी बन सकेंगे। आजकल तो यह इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान होता है कि मदरसों से निकलने वाले आतंकवादी होता हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मदरसों ने उर्दू को जिन्दा रखा है, जो का हुकूमत का था, जो काम इस मुल्क के लोगों का था। आपने उर्दू को खत्म करके एक तहजीब को, एक पूरे दौर को, एक पूरी तारीख को मिटा दिया। ज़बानें जो होती हैं, वे मुश्किल से बनती हैं, उसमें हज़ारों साल लग जाते हैं, लोगों को खून-ए-जिगर पिलाना पड़ता।

आज दुनिया में कोई भी कौम अपनी ज़बान से जानी जाती है चाहे वह फ्रैंच हो, चाहे जर्मन हो और यहां तक कि लोगों ने जो अपने देश बनाए हैं, वे भी ज़बानों के नाम से बने हैं। लेकिन एक ज़बान को मिटा दिया जाता है, इतनी जबरदस्त ज़बान, जिसमें इस उर्दू के अन्दर पूरी गंगा-जमुनी तहजीब, पूरे 2000 साल का हिन्दुस्तान निचुड़ कर आया था। उर्दू की बातें तो बहुत की जाती हैं, उसकी तारीफ भी की जाती है, लेकिन उर्दू को आहिस्ता-आहिस्ता, स्लो प्वॉइजन देकर इस मुल्क में खत्म किया गया, फिर चाहे वह बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो। उर्दू को जो हक मिलना चाहिए था, मुझे आज कहने दीजिए, वह नहीं मिला और वह हक इसलिए भी नहीं मिला कि उर्दू वाले भी पूरी ताकत से अपनी बात नहीं कहते हैं।

मान्यवर, यदि आप उर्दू को रोजगार से नहीं जोड़ेंगे, सर्व शिक्षा अभियान में यदि उर्दू को उसका हिस्सा नहीं देंगे तब तक बात नहीं बनेगी। आज हम उत्तर प्रदेश में उर्दू यूनिवर्सिटी बनाना चाह रहे हैं, वह क्यों बनाना चाह रहे हैं? वह इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी होगी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू यूनिवर्सिटी, उसके साथ, उस उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत हम बहुत से आई॰टी॰आई॰ भी शुरू कर सकेंगे, जो मदरसों में काम करेंगे, बहुत सारे मदरसे उससे एफिलिएट

हो सकेंगे। उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जब मदरसे को पास कर लेते हैं तब वे कहां जाएं? उन्हें किसी कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता, बी०ए० में दाखिला नहीं मिलता। बी०ए० का कॉलेज हम इसी यूनिवर्सिटी से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें मदद करने के बजाए आप उसमें रुकावट डाल रहे हैं। श्री जय राम रमेश जी, उसमें आप रुकावट डाल रहे हैं, वह रुकावट आप मत डालिए। ...(व्यवधान).....

श्री जय राम रमेश (आन्ध्र प्रदेश): महोदय, यह बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है।

श्री शाहिद सिद्दीकी: मैं माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं।

श्री जय राम रमेश: कानून के खिलाफ चान्सलर का एपाइंटमेंट हो रहा है, इसीलिए इस यूनिवर्सिटी के काम में रुकावट आ रही है।

श्री उपसभापति: इन्होंने बहुत बढ़िया उर्दू में बात की है। ...(व्यवधान)...

श्री शाहिद सिद्दीकी: मान्यवर, अब तो वह भी खिसक गया है। अब तो कम से कम, खुदा के लिए इस यूनिवर्सिटी को बनने दीजिए। मैं श्री देवगौड़ा जी को याद करना चाहता हूं, जब वे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक उर्दू यूनिवर्सिटी बनाई थी, लेकिन उससे पहले या उसके बाद उर्दू के लिए कोई काम नहीं हुआ। आज आपके पास भी कई राज्यों में सरकारें हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर एक-दो उर्दू यूनिवर्सिटीज शुरू कीजिए। उससे क्या होगा कि उर्दू वालों को रोजगार भी मिलेगा और उन्हें आगे जाने का मौका भी मिलेगा। जहां तक उर्दू के टीचर्स की बात है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो उर्दू में ग्रेजुएशन करते हैं, जो उर्दू में बी०ए० या एम०ए० करते हैं, कॉम्पिटीशन इतना ज्यादा है कि उन्हें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलता। जब हमें टीचर्स की जरूरत होती है, तो हमारे पास उर्दू का बी०एड० किया हुआ टीचर नहीं होता, इसलिए आप खास तौर पर उर्दू के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बनाइए। अगर आप उर्दू के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नहीं बनाएंगे तो उर्दू के टीचर आगे नहीं आ पाएंगे, इसी तरह से यह सारा सिलसिला जुड़ेगा और उर्दू मेन-स्ट्रीम में आएगी, जिससे इस मुल्क का भला होगा, इस मुल्क का फायदा होगा और इस मुल्क की शान बढ़ेगी।

हम पाकिस्तान से कहते हैं कि उर्दू तुम्हारी जबान नहीं है, यह हिन्दुस्तान की जबान है और यह हम फख्र से कहते हैं, सिर उठा कर कहते हैं और सच्चाई भी यही है कि यह हिन्दुस्तान की जबान है। पाकिस्तान जितना भी उसे अपनाना चाहे, दस सदियों तक भी वह उसे अपनी जबान नहीं बना सकता क्योंकि उर्दू, हिन्दुस्तान की जबान है और हिन्दुस्तान की जबान ही रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उर्दू को कोई खत्म नहीं कर सकता, उर्दू खत्म नहीं हुई है। आज महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आन्ध्र प्रदेश में, जहां-जहां भी उर्दू का कॉम्पिटीशन मकामी जबान से नहीं था और जहां उर्दू को

जबरदस्ती दबाया नहीं गया, वहां उर्दू के अन्दर इतना डायनामिज्म था कि उर्दू अपनी ताकत से अपने आप आगे बढ़ी। उर्दू वालों ने उर्दू अखबार वालों ने, उर्दू टीचर्स ने अपना पेट काट-काट कर उर्दू को पाला है।

महोदय, मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि उर्दू के अखबारों के साथ इतनी ज्यादती होती है क्योंकि हमारी कोई सरकारी नहीं है। गुजराती के अखबार को गुजरात की सरकार से इश्तिहार मिलते हैं, बंगाली अखबार को बंगाल की हुकूमत की पुश्त पनाही मिलती है, लेकिन उर्दू अखबारों को किसी की भी पुश्त पनाही और बैकिंग नहीं मिलती है, उन्हें कोई इश्तिहार नहीं मिलते हैं। उर्दू के अखबार वाले अपना पेट काट-काट कर इन उर्दू अखबारों को चलाते हैं, उसके लिए उन्हें आपको जोड़ना होगा। आप यह बिहार में कीजिए और मैं समझता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में कीजिए। मैं जानता हूं कि यहां पर मुझसे बेहतर बोलने वाले लोग हैं। ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: अभी 11 लोग बोलने वाले हैं, जरा समय का भी ख्याल रखिए।

श्री शाहिद सिद्दिकी: महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ...(व्यवधान)... मैं दाग के मशहूर शेर के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं—

''उर्दू है इसका नाम सभी जानते हैं 'दाग'

सारे जहां में धूम, हमारी जुबां की है,

लबो रुखसार गेसू बोलता है,

सरों पे चढ़ के जादू बोलता है,

अभी तहजीब जिन्दा है हमारी,

अभी ये शख्स उर्दू बोलता है''

†شری شاہد صدیقی ''اتر پردیش'' : ڈپٹی چیئرمین صاحب، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ہمیں اردو پر بات کہنے کا موقع دیا، کیونکہ کسی ہاؤس میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں کہ اردو پر بات ہو۔ ۵۵ سالوں سے اردو کا جو درد ہے، میں اسے یہاں بیان نہیں کرونگا، اردو کے

†Transliteration in Urdu Script.

ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں، میں وہ بیان نہیں کرونگا، کیون کہ وہ بہت لمبی داستاں ہے، اس کے لئے بہت وقت چاہئے۔ میں آج جو بات کرونگا، اس میں بہار میں اردو کی بھی بات کرونگا لیکن بہار میں جو اردو ہے وہ آئیسولیشن میں نہیں ہے۔ آپ صرف بہار میں اردو کو زندہ نہیں رکھ سکتے، اگر پورے ہندستان میں اردو کا قتل ہوگا۔ اگر بہار میں اردو کو زندہ رکھنا ہے تو روزگار سے اسے جوڑنا ہوگا، پورے ہندستان میں اردو کو اس کا حق دینا ہوگا۔ مہودے، اس لئے میں پورے ہندستان کے مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے بہار کی بات کرونگا۔ جو پچھلی باتیں ہیں۔ میں اس میں نہیں جاؤنگا۔ میں آج کی بات کرتا ہوں کہ جو کامن منیمم پروگرام بنا، اس میں وعدہ کیا گیا کہ اردو کو اس کا حق دیا جائے گا، جہاں پر ۱۰ فیصدی سے زیادہ اردو کے بولنے والے ہیں، وہاں پر اس کو دوسری زبان بنایا جائے گا، اسکولوں میں اس کے پڑھنے کا انتظام کیا جائے گا۔ میں منتری جی سے جاننا چاہوں گا کہ ایک سال ہوگیا، آپ نے اردو کے لئے، کامن منیمم پروگرام کے اس بنیادی مسئلے کو لاگو کرنے کے لئے، کیا قدم اٹھائے؟ آپ کے منتر الیہ نے کیا قدم اٹھائے ہیں؟ اردو کو انصاف دلانے کے لئے، دوسری زباں بنانے کے لئے آپ نے کیا اپنی شیڈیو لئے ہیں راشٹرپتی جی نے اپنے بھاشن میں اردو کو بڑھاوا دینے کی بات کہی تھی، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ بجٹ میں اردو کا نام لیا گیا، لیکن کوئی آوٹلن اس کے لئے نہیں کیا گیا، اس کے لئے کوئی رقم مقرر نہیں کی گئی۔ کب گیا کہ ٹیچرس لگائے جائیں گے۔ میرے عزیز آپ اردو کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے لئے کوئی کچھ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔

سب میرے چاہنے والے ہیں، مگر کوئی نہیں
میں خود اس ملک میں اردو کی طرح رہتا ہوں

مہودے، اردو کے ساتھ جو زیادتی ہوتی رہی ہے، اس میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اقلیتوں کی زبان ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اردو اقلیتوں کی زبان نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اردو

کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اقلیتوں کی زبان ہے اور اس لئے شاید اردو ختم ہوگئی، تو اقلیتیں بھی جو ہیں، وہ کمزور ہو جائیں گی ۔

ظلم اردو پر بھی ہوتا ہے اس نسبت سے
لوگ اردو کو مسلماں سمجھ لیتے ہیں

مہودے، غلط فہمی جو ہے، وہ دور ہونی چاہئے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ ایک بہت بڑا سروشکشا ابھیان کا پروگرام بنایا ہے، اس میں اردو کو آپ کہاں جگہ دے رہے ہیں؟ اردو کو اس میں کتنا حصہ ملنے والا ہے؟ کیونکہ اردو سے جڑے ہوئے لوگ، اردو کے پڑھنے والے لوگ جو ہیں، ان پر پچھلے ۵۶۔۵۵ سال میں ظلم ہوا ہے۔ اس لئے آج ان کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے، وہ زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو پورے دیش کو شکشت کرنا ہے، تعلیم یافتہ بنانا ہے، تو ان کے لئے آپ کو اردو پر زیادہ خرچ کرنا پڑیگا۔ جب تک آپ اس کے لئے رقم مقرر نہیں کریں گے، تب تک جو راجیہ کی سرکاریں ہیں، وہ اس پر عمل نہیں کرینگی۔

مہودے، یہ ضروری ہے کہ اردو کو روزگار سے جوڑا جائے۔ جب تک اردو کو روزگار سے نہیں جوڑیں گے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ اردو کو روزگار سے آپ کیسے جوڑیں گے؟ آپ اردو کا ٹی وی چینل شروع کیجئے۔ ساری زبانوں کے شروع ہو گئے، اُڑیہ کا ہو گیا، بنگلہ کا ہو گیا، لیکن اردو کا چینل شروع کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اردو کی کمزوری یہ ہے کہ اردو پورے ہندستان میں بولی جاتی ہے۔ یہ ہندستان کی چھٹی سب سے بڑی زبان ہے۔ کشمیر سے تمل ناڈو تک اردو کے اسکول ہیں، اردو کے بولنے والے ہیں، اردو کے چاہنے والے ہیں، لیکن ابھی بھی کشمیر کے علاوہ کوئی اسٹیٹ اس میں آگے نہیں ہے اس لئے اردو کے لئے کوئی مانگ کرنے والا نہیں ہے، اردو کے لئے کوئی لڑنے والا نہیں ہے۔ اردو کا ٹی وی چینل آپ شروع کریں گے، تو اس سے روزگار ملے گا، اردو کا ریڈیو اسٹیشن شروع کریں گے تو اس

سے روزگار ملے گا، اردو کا ریڈیو اسٹیشن شروع کریں گے، تو اس سے بھی روزگار ملیگا۔ اس سب سے بڑھ کر میں یہ کہنا چاہونگا کہ جب تک اردو کے ٹیچرس نہیں ہونگے، جب تک اردو کا انتظام نہیں ہوگا، نہ روزگار ملیگا اور نہ اردو ہوگی۔

بہار میں جب ۱۹۸۶ میں کانگریس کی سرکار تھی، جگن ناتھ مشر جی نی، میں ان کو آج یاد کرتا ہوں اور ان کو بدھائی دیتا ہوں، کہ انہوں نے اسے دوسری زبان کا درجہ دیا تھا اور ہمیں اندھیرے میں ایک امید کی کرن نظر آئی تھی کہ اردو کو ایک نئی زندگی ملنے والی ہے۔ جب ۱۹۸۶ میں اسے دوسری زبان بنایا گیا، تو کیا ہوا؟ بہار میں ۱۹۸۶ میں جگن ناتھ مشر جی نے اردو کو جب دوسری زبان بنایا، تو ۶۰۰ ٹرانسلیٹر لگائے گئے، ۳۰۰ ٹرانسلیٹر اور ۳۰۰ اسسٹنٹ ٹرانسلیٹر، لیکن آج وہ ٹرانسلیٹر اردو کا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ فائلنگ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ان سے اردو کا کام نہیں لیا جاتا اور اس کے بعد سے تو بہار میں کوئی اردو کا ٹرانسلیٹر اپائنٹ ہی نہیں کیا گیا، جسے آپ کہتے ہیں بحال نہیں کیا گیا۔ پچھلے ۳۰ سال کے اندر آپ نے اردو کا کوئی ٹرانسلیٹر بحال نہیں کیا، ان ۶۰۰ کے بعد میں اور ان میں بھی جو ریٹائر ہوئے، وہ جاتے گئے۔ یہ ٹرانسلیٹر بی اے گریجویٹ تھے، لیکن گریجویٹ کے ساتھ کیا زیادتی کی، کہ ان کو آپ نے جو تنخواہ دی، جو گریڈ دیا، وہ انٹر والے کو دیا جاتا ہے۔ دوسرا اگر کوئی کسی پوسٹ پر گریجویٹ آرہا ہے تو اس کو تنخواہ دوسری ملیگی اور اردو کا جو گریجویٹ ہوگا اس کو تنخواہ دوسری ملیگی۔ آپ نے صاف کر دیا کہ اردو کو ہم دوسرے، تیسرے، چوتھے، درجے کی زبان سمجھتے ہیں، اردو پڑھانے والوں کو ہم دوسرے درجے کا سمجھتے ہیں۔ اردو میں امتحان دینے والے اور کام کرنے والے کو برابر کا حق دینے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم اس کے لئے بھی تیار تھے، لیکن وہ بھی آپ نے نہیں کیا۔ جگن ناتھ مشر جی نے اعلان کیا تھا تمام تھانوں کے لئے، چونکہ تھانوں کا کام بہار میں ہی نہیں، پورے ہندستان کے اندر، نارتھ انڈیا میں سارے

تھانوں کا کام، پولیس اسٹیشن کا کام، کورٹ کا کام ۱۹۴۷ تک، بلکہ ۵۶۔۱۹۵۵ تک اردو میں ہوتا رہا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ جب اردو کے لوگ لگائے نہیں گئے، تو پرانے ساتے جو ریکارڈ پڑے ہوئے ہیں، ان ریکارڈ میں کوئی جا نہیں سکتا، اس لئے مشرا جی نے کہا تھا کہ ہر تھانے میں کم سے کم ایک منشی یا ایک آدمی اردو جاننے والا لگایا جائے گا۔ میں آپ سے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہار کے اندر کہیں کسی تھانے میں اردو جاننے والے کو اپائنٹ نہیں کیا گیا۔ جب میں بہار کی بات کر رہا ہوں، تو یہ مان کر چلتا ہوں کہ پورے دیش کی بات کر رہا ہوں، جہاں جہاں اردو ہے۔

مہودے، اس وقت چونکہ بہار کا سوال ہے۔ اس لئے میں بہار پر ہی زور دونگا۔ آپ کچھ اسکولوں میں جو ٹیچرس لگانے والے تھے۔ وہ اردو کے ٹیچرس آپ نے نہیں لگائے۔ آج بھی حالت یہ ہے کہ ۹۰۰۰ جگہ خالی ہیں اردو کے ٹیچرس کی، یعنی ۹۰۰۰ لوگوں کو آپ نوکری دے سکتے تھے۔ اردو والے اردو میں بی اے، ایم اے کرنے کے بعد بھی بھوکوں مر رہے ہیں۔ انہیں اپنا پیٹ کاٹ کر اردو کو زندہ رکھنا پڑ رہا ہے، لیکن انہیں نوکری نہیں دی گئی۔ بہار کے اندر ۹۰۰۰ ٹیچرس کی جگہ خالی ہے، وہ ٹیچرس نہیں لگائے گئے۔ بہار میں ۹۵ فیصد جو گورنمنٹ ہائی اسکولس ہیں، ان میں اردو ٹیچر نہیں ہیں۔ اردو زبان کے جو بچے ہیں اور جو اردو پڑھنا چاہتے ہیں، انہیں اردو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ جو ٹیچر ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کی جگہ دوسرے اردو کے ٹیچر نہیں لگائے جا رہے ہیں، تو صورت حال یہ ہے۔

مدرسوں کے لئے آپ نے کہا تھا کہ ۲۹۰۰ مدرسے منظور شدہ ہیں لیکن ان مدرسوں کے استاد بھی ۱۵ سالوں سے سڑکوں پر ہیں، ان کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، پچھلے دو سال سے انہیں تنخواہیں نہیں ملیں۔ آپ نے بیس سال پہلے بہار میں مظہر الحق عربی۔ فارسی۔ اردو یونیورسٹی بنانے کا اعلان کیا تھا، وہ آج تک کتابوں میں ہی ہے۔ پچھلے دنوں سنا کہ کسی شرف الدین صاحب کو وائس چانسلر بنا دیا گیا، لیکن ابھی تک ان کا کوئی آفس نہیں ہے، کوئی کیمپس نہیں ہے، یہ سب آپ نے اردو کے ساتھ کیا۔ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مدرسوں کی بات کرتے ہیں، اگر سارے مدرسوں کو کسی اردو یونیورسٹی سے ایفی لی ایٹ کر دیا جائے، تو ان

مدرسوں کے بچے گریجویٹ ہوکر نکلیں گے۔ وہ جب ان مدرسوں سے پڑھ کر کالج میں آئیں گے، تو گریجویشن کرسکیں گے، روزگار لے سکیں گے اور آگے جاکر یوزفل شہری بن سکیں گے۔ آج کل تو یہ الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے کہ مدرسوں سے نکلنے والے آتنکوادی ہوتے ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدرسوں نے اردو کو زندہ رکھا ہے، جو کام حکومت کا تھا، جو کام اس ملک کے لوگوں کا تھا۔ آپ نے اردو کو ختم کرکے ایک تہذیب کو، ایک پورے دور کو، ایک پوری تاریخ کو مٹادیا۔ زبانیں جو ہوتی ہیں، وہ بہت مشکل سے بنتی ہیں، اس میں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں، لوگوں کو خونِ جگر پلانا پڑتا ہے۔

آج دنیا میں کوئی بھی قوم اپنی زبان سے جانی جاتی ہے چاہے وہ فرینچ ہو، چاہے جرمن ہو اور یہاں تک کہ لوگوں نے جو اپنے دیش بنائے ہیں، وہ بھی زبانوں کے نام سے بنے ہیں۔ لیکن ایک زبان کو مٹادیا جاتا ہے، اتنی زبردست زبان، جس میں اس اردو کے اندر پوری گنگا جمنی تہذیب، پورے ۲۰۰۰ سال کا ہندستان نچوڑ کر آیا تھا۔ اردو کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، اس کی تعریف بھی کی جاتی ہے، لیکن اردو کو آہستہ آہستہ، سلو پوائزن دیکر اس ملک میں ختم کیا گیا پھر چاہے وہ بہار ہو، اتر پردیش ہو، دہلی ہو۔ اردو کو جو حق ملنا چاہئے تھا، مجھے آج کہنے دیجئے، وہ نہیں ملا اور وہ حق اس لئے بھی نہیں ملا کہ اردو والے بھی پوری طاقت سے اپنی بات نہیں کہتے ہیں۔

مانیور، اگر آپ اردو کو روزگار سے نہیں جوڑیں گے، سرشکشا ابھیان میں اگر اردو کو اس کا حصہ نہیں دیں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ آج ہم اتر پردیش میں اردو یونیورسٹی بنانا چاہ رہے ہیں، وہ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس لئے بنانا چاہ رہے ہیں کہ اردو یونیورسٹی ہوگی، وہ کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ وہ اس لئے بنانا چاہ رہے ہیں کہ اردو یونیورسٹی ہوگی، مولانا محمد علی جوہر اردو یونیورسٹی، اس کے ساتھ، اس اردو یونیورسٹی کے تحت ہم بہت سے آئی ٹی آئی بھی شروع کرسکیں گے، جو مدرسوں میں کام کریں گے، بہت سارے مدرسے اس سے ایفی لی ایٹ ہوسکیں گے، ان مدرسوں میں پڑھنے والے بچے جب مدرسے سے پاس کر لیتے ہیں تب وہ کہاں جائیں؟ انہیں کسی کالج میں داخلہ نہیں ملتا، بی ایڈ

میں داخلہ نہیں ملتا۔ بی ایڈ کا کالج ہم اسی یونیورسٹی سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس میں مدد کرنے کے بجائے آپ اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ شری جے رام رمیش جی، اس میں آپ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، وہ رکاوٹ آپ مت ڈالئے.....مداخلت.....

شری جے رام رمیش : مہودے، یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے۔

شری شاہد صدیقی : میں معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں۔

شری جے رام رمیش : قانون کے خلاف چانسلر کا اپائنٹمنٹ ہو رہا ہے، اسی لئے اس یونیورسٹی کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے۔

شری اُپ سبھاپتی: انہوں نے بہت بہت بڑھیا اردو میں بات کی ہے .....مداخلت.....

شری شاہد صدیقی : مانیور، اب تو وہ بھی وڈ ڈرا ہو گیا ہے۔ اب تو کم سے کم، خدا کے لئے اس یونیورسٹی کو بننے دیجئے۔ میں شری دیوگوڑا جی کو یاد کرنا چاہتا ہوں، جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے، انہوں نے ایک اردو یونیورسٹی بنائی تھی، لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد اردو کے لئے کام نہیں ہوا۔ آج آپ کے پاس بھی کئی راجیوں میں سرکاریں ہیں۔ میں مانیے منتری جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ایک دو اردو یونیورسٹیز شروع کیجئے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اردو والوں کو روزگار بھی ملے گا اور انہیں آگے جانے کا موقع بھی ملے گا۔ جہاں تک اردو کے ٹیچرس کی بات ہے، سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ جو اردو میں گریجویشن کرتے ہیں، جو اردو میں بی اے یا ایم اے کرتے ہیں، کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ انہیں ٹیچرس ٹریننگ کالج میں داخلہ نہیں ملتا۔ جب ہمیں ٹیچرس کی ضرورت ہوتی ہے، تو ہمارے پاس اردو کا بی ایڈ کیا ہوا ٹیچر نہیں ہوتا۔ اس لئے آپ خاص طور پر اردو کے ٹیچرس ٹریننگ کالج بنائیے۔ اگر آپ اردو کے ٹیچرس ٹریننگ کالج نہیں بنائیں گے تو اردو کے ٹیچر آگے نہیں آپائیں گے، اسی طرح سے یہ سارا سلسلہ جڑے گا اور اردو مین اسٹریم میں آئے گی، جس سے اس ملک کا بھلا ہوگا، اس ملک کا فائدہ ہوگا اور اس ملک کی شان بڑھے گی۔

ہم پاکستان سے کہتے ہیں کہ اردو تمہاری زبان نہیں ہے، یہ ہندستان کی زبان ہے اور یہ ہم فخر سے کہتے ہیں، سر اٹھا کر کہتے ہیں اور سچائی بھی یہی ہے کہ یہ ہندستان کی زبان ہے۔ پاکستان جتنا بھی اسے اپنانا چاہے، دس صدیوں تک بھی وہ اسے اپنی زبان نہیں بنا سکتا کیونکہ اردو، ہندستان کی زبان ہے اور

ہندستان کی زبان ہی رہے گی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کو کوئی ختم نہیں کرسکتا، اردو ختم نہیں ہوئی ہے۔ آج مہاراشٹر میں، کرناٹک میں، آندھراپردیش میں، جہاں جہاں بھی اردو کا کمپٹیشن مقامی زبان سے نہیں تھا اور جہاں اردو کو زبردستی دبایا نہیں گیا، وہاں اردو کے اندر اتنا ڈائنامزم تھا کہ اردو اپنی طاقت سے اپنے آپ آگے بڑھی۔ اردو والوں نے، اردو اخبار والوں نے، اردو ٹیچر نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اردو کو پالا ہے۔

مہودے، میں سرکار سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اردو کے اخباروں کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے کیونکہ ہماری کوئی سرکار نہیں ہے۔ گجراتی کے اخبار کو گجرات کی سرکار سے اشتہار ملتے ہیں، بنگالی اخبار کو بنگال کی حکومت کی پشت پناہی ملتی ہے، لیکن اردو اخباروں کو کسی کی بھی پشت پناہی اور بیلنگ نہیں ملتی ہے۔ انہیں کوئی اشتہار نہیں ملتے ہیں۔ اردو کے اخبار والے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر ان اردو اخباروں کو چلاتے ہیں، اس کے لئے انہیں آپ کو جوڑنا ہوگا۔ آپ یہ بہار میں کیجئے اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندستان میں کیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر مجھ سے بہتر بولنے والے لوگ ہیں۔.....مداخلت.....

شری اُپ سبھاپتی: ابھی گیارہ لوگ بولنے والے ہیں، ذرا وقت کا خیال رکھئے۔

شری شاہد صدیقی : مہودے، میں اپنی بات سماپت کرتا ہوں .....مداخلت.....میں داغ کے مشہور شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں ۔

اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ
سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے
اور لب ورخسار گیسو بولتا ہے
سروں پہ چڑھ کر جادو بولتا ہے
ابھی تہذیب زندہ ہے ہماری
ابھی یہ شخص اردو بولتا ہے

एक माननीय सदस्य: क्या आप उर्दू में कुछ बोलेंगे ...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: जी हां, बोलूंगा। ...(व्यवधान)... The Chair has an innerent right to put questions.

श्री तरलोचन सिंह (हरियाणा): माननीय उपसभापति जी, बहुत शुक्रिया। मुझे इस बात की खुशी भी है और गम भी है, खुशी इस बात की है कि बड़ी मुश्किल से उर्दू के लिए बोलने का मौका मिला और दु:ख यह है कि वह जुबान, जिसने हिन्दुस्तान की आजादी को लाने में सबसे ज्यादा काम किया, आज उसकी हिफाजत के लिए हम लोग इस हाउस में खड़े हो कर कहें कि इसकी मदद करो। यह वही जबान है, जिसने 'इंकलाब' लफ्ज दिया था और वह ''इंकलाब जिंदाबाद'' का लफ्ज देने वाले अकेले उर्दू वाले ही नहीं थे, साउथ में भी वही लफ्ज था। यह वही जबान है जो आज भी कहती है कि ''सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्ता हमारा'' और बाद में वही कौमी तराना बना। यह वही जबान है जिसमें हम जब किसी जगह जाते हैं तो ''सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजु-ए-कातिल में है'' गाया जाता है और हिन्दुस्तान में जब किसी जगह जरूरत पड़ती है कि लोगों में जोश दिलाया जाए या कहीं यह कहना पड़ता है कि देश भक्ति कहां है, तो फिर उर्दू को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब उर्दू के लिए कुछ करना हो तो होता कुछ नहीं है उर्दू के दो दुश्मन हैं, मैं काफी समय से उर्दू के लिए काम कर रहा हूं, एक तो वे जिन्होंने इसे एक फिरके की जबान बना दिया और वह एक परचम लेकर खड़ा हो गया कि यह हमारी जबान है, हमें दो और दूसरे पोलिटिकल पार्टी वाले जो वोट बैंक बनाने के लिए इस जबान का इस्तेमाल करने लगे जबकि वहां इसका कुछ काम नहीं था। इसलिए मैं एक तो यह अर्ज करना चाहता हूं कि उर्दू एक फिरके की जबान नहीं है। मुझे याद है कि जब ज्ञानी जैल सिंह जी होम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने उर्दू में ओथ लिया, तो लोग कहने लगे कि यह क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि मेरी तो जबान ही उर्दू है। जब चौधरी देवी लाल उप प्रधान मंत्री थे, तो जो भी उनके साथ काम करते थे, उन्हें देखते थे, वे उर्दू में ही नोट्स मांगते थे और उर्दू में ही काम करते थे। ...(व्यवधान)... जी हां, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हम भूल जाते हैं फिराक गोरखपुरी को, भूल जाते हैं आनन्द नारायण मुल्ला को, जगन्नाथ आजाद को या आज के लोगों की बात करें तो डा० गोपीचंद नारायण को, जाकिर को, जमनादास अख्तर को। आज भी जो उर्दू का रोजाना सबसे बड़ा अखबार है वह मुसलमान नहीं निकालते, वह जालन्धर से छपता है और उसका नाम है ''हिन्द समाचार''। largest circulated Urdu newspaper is still from Punjab और वहां मुसलमान नहीं रहते हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि उर्दू जबान को कभी भी एक फिरके की जबान न समझा जाए और जब तक हम इस गलतफहमी से नहीं निकलेंगे, हम इस जबान की तरक्की नहीं कर पाएंगे।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि जितना यह नॉर्थ इंडिया है, शुमाली हिन्दुस्तान, इसका सारा रिकार्ड उर्दू जबान में है। जितने भी पटवारियों के पास जो कुछ है भी है, वह उर्दू में है या आज भी यदि कहीं कोर्ट या कचहरी में जरूरत पड़ती है तो वह उर्दू में आता है। यदि उर्दू की पढ़ाई खत्म हो गई तो ये जो उर्दू के सारे रिकॉर्ड हैं, ये कौन पढ़ेगा?

आजकल हमारे दो पंजाबों की दोस्ती चल रही है, वे हैं हिन्दुस्तान और पाकिस्तान। इस दोस्ती को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें उर्दू की जबान को कायम रखना होगा, वरना हम आपस में क्या दोस्ती करेंगे और मैं तो इससे भी आगे जाना चाहता हूं, मैंने नोट भेजा है, अगर हमारे देश से परशियन खत्म हो गई तो हमारी तारीख से क्या वापस आएगा और उसे कौन पढ़ेगा? मैं तो सिखों को कहता हूं, हमारे गुरू ग्रंथ साहिब में परसियन है, महाराजा रणजीत सिंह, जो हमारे सिख बादशाह थे, उनकी कोर्ट लैंग्वेज परसियन थी, पटियाला रियासत में सबकी परसियन कोर्ट लैंग्वेज थी, जितने archieves हैं, सभी परसियन में हैं। मैं रिकमंड करना चाहता हूं कि ऐटलीस्ट जो पंजाब में यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें परसियन एक कम्पलसरी लैंग्वेज रखिये। वहां पर उनको इनसेंटिव दें, ताकि लोग परसियन पढ़ते रहें, वरना हमारे यह स्कालर जो उनसे संबंधित हैं वे अपना रिकार्ड देखने में असमर्थ होंगे।

सर, अभी मेरे दोस्त ने जो उर्दू के लिए कहा, सच्चाई तो यह है कि जिस दिन यहां पर यह सवाल आया था, उस दिन टैक्स्ट बुक्स की बात चली थी और मंत्री जी ने कहा था कि सब ऐवेलेबल हैं। दो दिन के बाद अंग्रेजी हिन्दुस्तान टाइम्स अखबार में उर्दू एकाडेमी जो दिल्ली की है, जिसके जिम्मे यह किताबें बांटना है, उनका एक बयान छपा कि हमारे पास किताबें नहीं हैं, हमारे पास नहीं आइये। जिन्होंने किताबें देनी हैं, वे कह रहे हैं कि किताबें नहीं है, लोग हमें तंग कर रहे हैं और हालत यह है कि जो किताबें दसवीं और बारहवीं की साइंस, सोशल साइंस, मैथिमेटिक्स, ज्योग्राफी की बिल्कुल किताबें मार्केट में नहीं हैं, और छोटी जमातों की भी टैक्स्ट बुक्स नहीं हैं, उर्दू की टैक्स्ट बुक्स की ऐवेलेबिलिटली भारत में क्या दिल्ली में भी नहीं है। यहां पर मंत्री जी बैठे हैं, आप इसका कोई उपाय करिये। दिल्ली में यह हालत है कि यहां उर्दू बोलने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, परसेंटवाइज दिल्ली शहर में सबसे ज्यादा अब भी उर्दू जुबान है और यहां सरकार के 1400 स्कूल हैं, लेकिन उर्दू के लिए सिर्फ 20 स्कूल हैं। यह हमारा कम्पेरिजन है। जमुना पार जहां दिल्ली की सत्तर परसेंट आबादी रहती है, वहां पर सिर्फ एक स्कूल है जो उर्दू मीडियम है, उसमें सात हजार स्टूडेंट हैं और दूसरा स्कूल दिल्ली वाले जमुना पार नहीं खोल सके। जितने टीचर्स की डिमांड दिल्ली में है, इतने टीचर्स की वेकेंसीज हैं, जिनको सरकार ने भरा नहीं है। अभी चार दिन पहले बिहार के स्कूलों के बारे में आया था कि वहां तीन हजार नब्बे वेकेंसीज खाली पड़ी हैं, जिसमें उर्दू टीचर्स चाहिएं और सरकार ने ये वेकेंसीज़ भरी नहीं हैं। कभी किसी कचहरी का मसला ले लेते हैं और कभी कोई और मसला ले लेते हैं। उर्दू टीचर्स की ऐवेलेबिलिटी बहुत कम है, टैक्स्ट बुक्स बहुत कम हैं, इसके अलावा मेरा यह कहना है कि उर्दू में वोकेशनल कोर्स नहीं हैं।

सरकार उर्दू टाइप राइटिंग के, उर्दू स्टेनोग्राफी के, प्रूफ रीडिंग के, प्रिंटिंग टेक्नालॉजी के इंतजाम करे। जैसे हम हिन्दी के लिए अवार्ड देते हैं, उर्दू अवार्ड भी उसके बराबर का होना चाहिए और हर साल उर्दू के लिए अवार्ड दिया जाये। अभी आपने एक नेशनल काउंसिल आफ प्रोमोशन आफ उर्दू लैंग्वेज बना रखी है, लेकिन वह काम क्या करती है? अभी-अभी कुछ दिन पहले मैंने उस काउंसिल के बारे में पढ़ा था। अभी एक कमेटी बनाई कमेटी की रिपार्ट आई और उस कमेटी में वे लोग थे, जिन्हें उर्दू जुबान नहीं आती है। उसका बजट दस करोड़ रुपये है। उसमें से एक करोड़ 66 लाख रुपये स्टाफ पर खर्च होते हैं। अभी उन्होंने शुरू किया है कि उसी बजट से वे कम्प्युटर भी बाटेंगे, उसी बजट से वे अरबो की क्लासेज भी करेंगे। अगर सरकार ने यह करना है तो उसके लिए अलहिदा बजट दिया जाए इसके अलावा जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल हैं, उनमें उर्दू का कोई काम नहीं है, अगर कहीं है तो वहां स्टाफ नहीं है। इसके लिए मेरी आप से दर्ख्वास्त है कि यह किया जाए। इस वक्त हिंदुस्तान में जितनी रियासतें हैं, उनमें से सिर्फ 15 रियासतों ने उर्दू एकादमी बनाई है। बाकी जगह उर्दू एकादमी नहीं है और जहां पर है भी तो वहां पर इतना कम सरमाया उनके पास है, कि वह काम कर ही नहीं पाती है। इसके अलावा मैं जो अंतिम बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि मसला तो उर्दू का है, लेकिन यहां सारी अक्लियतें जुबानें खत्म हो रही हैं। उर्दू के लिए तो फिर भी पॉलिटिकल प्रैशर है, आपको वोट बैंक का भी फिक्र है। पंजाबी जुबान के लिए पंजाब से बाहर भारत सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं करती। पंजाबी सैकेंड लैंग्वेज है दिल्ली में, एक रुपए का भी बजट नहीं है। हिमाचल और हरियाणा पंजाब से निकले हैं, जहां पंजाबी कम्पलसरी थी अब उनमें पंजाबी जुबान बिल्कुल नहीं है। अभी 6 महीने हरियाणा में पंजाबी को सैकेंड लैंग्वेज किया गया। हिमाचल सरकार ने तो यह किया है, माइनोरिटीज कमीशन ने यह रिकमेंड किया कि आप तो पंजाब से आए हो, पंजाबी लैंग्वेज को ऑप्सनल कर दो, यह उनकी केबिनेट में गया, फिर असेम्बली में पास किया, हम पंजाबी नहीं कर सकते। पंजाबी जुबान का यह हाल है। एक बौद्ध कौम है, वह भी माइनारिटी कम्युनिटी है। उनकी बौद्धि जुबान है, आज तक भारत सरकार ने उनकी बौद्धि जुबान को रिकमंडेशन नहीं दी है। सारे हिमाचल में सिक्किम से लेकर के लद्दाख तक बौद्धिष्ठ हैं और इनकी लैंग्वेज का हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं यह दरख्वास्त करता हूं कि यदि हम चाहते हैं तो इसको पॉलिटिक्स से बाहर निकालें, सीरियस होकर सरकार उर्दू के लिए और बाकी माइनारिटीज के लिए काम करे और सही रूप में करे। सिर्फ कमेटियां बना दें या 5-6 और कमीशन बना दें, 5-6 कमेटीज़ बना दें, उसका भी खर्चा शो करके एक साल के बाद रिकमेंडेशन आएगी-क्या पचास साल में कमेटियों में ही रहना है? किसको नहीं पता कि उर्दू का क्या महत्व है, उर्दू को चाहने वाले कौन हैं? इतना कहकर मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे (पश्चिमी बंगाल): माननीय उपसभापति महोदय, हम आज उर्दू भाषा के लिए यहां बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मुझे खुशी भी है और गम भी है कि बहुत देर से हम किसी भाषा, किसी जुबान पर यहां चर्चा करने के लिए आए हैं। यहां, पर अपने 12 वर्ष के

समय में मुझे याद है कि एक बार हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, उर्दू पर बातचीत की थी और वह विश्वविद्यालय किस रूप में काम कर रहा है, यह खोज-खबर लेने के बाद पता चला है कि जिस रूप में हमने यहां सोचा था कि उन्नति करेगा, वैसे नहीं कर पाया। उर्दू जुबान को जब बात आती है तो मुझे लगता है कि इसके साथ पूरी एक तहजीब जुड़ी हुई है और हम, जो हिन्दी पढ़ने-पढ़ाने वाले लोग हैं, उनके साथ उर्दू का उतना ही संबंध है जितना यहां आपस में बैठे हुए जो सांसद हैं, उनका आपसी अंतरंग संबंध है। हिन्दी और उर्दू का संबंध भी वैसा ही है। सर, मैं एक शेर के साथ अपनी बात कहना चाहूंगी। ऐसा न हो, बहुत देर हो जाए और हम मीर की शब्दावली में यह कहें कि

खत्म होने को जब आयी जिंदगी की दास्तां,

उनकी फरमाइश हुई है, इसको दोबारा कहें।

ऐसा न हो कि सब कुछ खत्म हो जाए और बार-बार हम यह कहते रहें। सिद्दीकी साहब आज एक बहुत अच्छी बात यहां पर लेकर आए हैं। मैं जिस प्रदेश से आती हूं, पश्चिमी बंगाल, वहां चाहे जिस भी कारण से हो, उर्दू के लिए हम लोग काफी काम करते हैं। हमारी उर्दू एकेडमी है। अखबार की बात हुई कि advertisements सरकारी नहीं मिलते हैं। हमारा "आबशार" अखबार है, उसको सरकारी advertisements हिन्दी अखबारों से भी पहले मिलते हैं। एक और बात कहना चाहती हूं। मदरसा बोर्ड बनाकर मदरसे की शिक्षा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ वहां जोड़ दिया गया है और स्कूल सर्विस कमीशन, कालेज सर्विस कमीशन की जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें उर्दू को उतनी ही प्रायोरिटी मिलती है जितनी हिन्दी को मिलती है। इसलिए मैं चाहूंगी कि बिहार में भी इस तरह मदरसा बोर्ड बनाकर ...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य: बिहार में है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडे: उर्दू की शिक्षा को मुख्य धारा के साथ जोड़ दिया जाए। अगर नहीं है तो मुख्य शिक्षा के साथ जोड़कर उसकी बेहतरी के लिए भी उतना ही बात सोची जाए। अगर सब कुछ वहां है तो फिर आज जो बात उठी है, वह उठनी ही नहीं चाहिए थी। जगन्नाथ मिश्र जी ने जिस उर्दू यूनिवर्सिटी की बात की थी, मज़हर-उल-हक, उसका प्रस्ताव अभी भी अगर कागज पर है तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि कब तक वह असलियत में उतर आएगा? एनसीपीएल का बजट अभी तक 11 करोड़ है। 11 करोड़ का बजट बहुत कम है। उर्दू की बेहतरी के लिए क्या इस बजट को और अधिक बढ़ाया जाएगा? गांवों में शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। मैं यह पूछना चाहूंगी कि कितने प्रतिशत शिक्षक शिक्षा मित्र की हैसियत से उर्दू के लिए नियुक्त किए गए हैं? उर्दू कंसलटेटिव बोर्ड बनाया गया था, जिसका काम था नीतियों का क्रियान्वयन करना,

लेकिन वह पूरी तरह सक्रिय नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, इसके चेयरमैन का पद भी अब तक खाली है। वह चेयरमैन का पद कब तक भर लिया जाएगा? अभी हमारे एक सांसद मित्र ने यह बताया कि देश की आजादी की लड़ाई से उर्दू का बहुत गहरा सादका था। ''इंकलाब'' शब्द उर्दू से ही हमने अपनाया। मैं अपनी ओर से यह कहना चाहूंगी कि हिन्दी भाषा की बेहतरी के लिए जितना कुछ काम किया जा रहा है, अगर उसका पचास प्रतिशत भी उर्दू के लिए किया जाए तो उर्दू के लिए हमें यहां चर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। राजभाषा की दृष्टि से केवल हिन्दी को बढ़ावा दिया जाता है और सभी भारतीय भाषाएं, केवल उर्दू ही नहीं, बहुत ही उपेक्षा की शिकार होती हैं। मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करना चाहूंगी कि सभी भारतीय भाषाओं की बेहतरी के लिए एक कमेटी बनायी जाए और सबके लिए बजट आबंटित किया जाए। उर्दू वह जुबान है, जिसके बारे में हमारे शायरों ने लिखा:

वहीं वहीं इंसानियत हुई महसूस,

जहां-जहां भी चले मेरी जुबां के लोग।

जहां-जहां उर्दू जुबां के लोग हैं, इंसानियत वहां-वहां हमेशा महसूस की जाती रही है और महसूस की जाती रहेगी। मैं इन कुछ प्रश्नों और सुझावों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि हमें और इंतजार न करना पड़े। उर्दू की बेहतरी के लिए आप कुछ नयी योजना लेकर आइए। धन्यवाद।

MESSAGES FROM LOK SABHA

The Bihar Value Added Tax Bill, 2005

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Ruels of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Bihar Value Added Tax Bill, 2005, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 11th May, 2005.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table of the House.